चुनाव अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

क्रमांकः एफ.3(1)(1)प्रथम/निर्वा/2023/3996 जयपुर, दिनांकः 24/8/23

प्रेषकः मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषितिः 1. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर), राजस्थान।

2. समस्त रिटर्निंग अधिकारी,
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, राजस्थान।

विषय :विधानसभा आम चुनाव, 2023 – Making election campaign eco friendly-Consolidated instruction-regarding.

प्रसंग :भारत निर्वाचन आयोग का पत्र क्रमांक 3/ER/2023/SDR/VOL.II दिनांक 18 अगस्त, 2023 एवं विभागीय पत्र क्रमांक 3117 दिनांक 19.07.2023 के क्रम में।

सन्दर्भः

1. Commission's letter no. 4/3/99/JS.II, dated 16.07.1999
2. Commission's letter no. 4/3/2003/JS.II/Vol.I, dated 01.05.2003
3. Commission's letter no.4/3/2004/ JS.II/Vol.I, dated 11.03.2004
4. Commission's letter no. 4/3/2006/JS.II, dated 16.03.2006
5. Commission's letter no. 4/3/2016/SDR, dated 05.04.2016
6. Commission's letter no. 4/3/2019/SDR, dated 26.02.2019
7. Commission's letter no. 3/ER/2019/SDR/VOL.II, dated 19.03.2019
8. Commission's letter no. 3/ER/2019/SDR/VOL.II, dated 02.04.2019 (Sent to CEO Kerala), and
9. Commission's letter no. 3/ER/2019/SDR/VOL.II, dated 09.09.2021

महोदय,

भारत निर्वाचन आयोग ने चुनावों को eco friendly बनाने हेतु अपने समय –समय पर जारी अपने सन्दर्भित दिशा–निर्देशों के क्रम में संकलित दिशा–निर्देश प्रासंगिक पत्र द्वारा जारी किये है एवं निर्देशित किया है कि आज की दुनिया में, पर्यावरण संबंधी चिंताएँ अधिक महत्वपूर्ण हो गई हैं, चुनाव आयोग भी चुनावों में non-biodegradable सामग्रियों के उपयोग के कारण होने वाले पर्यावरणीय खतरों के मुद्दे पर बहुत चिंतित है। आयोग 1999 से सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से चुनाव प्रचार के दौरान पोस्टर, बैनर आदि तैयार करने के लिए प्लास्टिक/पॉलिथीन के उपयोग से बचने का आग्रह करता रहा है।

2. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक G.S.R. 571(E) दिनांक 12.08.2021 का पैरा 4(बी) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 को संशोधन करते हुए प्रदान करता है कि–

"(2) पॉलीस्टाइनिन और विस्तारित पॉलीस्टाइनिन सहित निम्नलिखित एकल उपयोग प्लास्टिक का निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग 1 जुलाई, 2022 से प्रतिबंधित किया जाएगा: –

(ए) प्लास्टिक की sticks के साथ ear buds, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की sticks, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी sticks, आइसक्रीम sticks, सजावट के लिए पॉलीस्टाइनिन (थर्मोकोल);

(बी) प्लेट, कप, गिलास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डिब्बे, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट के पैकेट के चारों ओर लपेटने या पैक करने वाली फिल्म, 100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, स्टिरर।

(3) उप–नियम (2) (बी) के प्रावधान कंपोस्टेबल प्लास्टिक से बनी वस्तुओं पर लागू नहीं होंगे।

(4) पॉलीस्टाइनिन और विस्तारित पॉलीस्टाइनिन, वस्तुओं सहित कैरी बैग, प्लास्टिक शीट या उसके समान, या प्लास्टिक शीट और बहुस्तरीय पैकेजिंग और एकल–उपयोग प्लास्टिक से बने कवर के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाली कोई भी अधिसूचना जो इस अधिसूचना के बाद जारी की गई, इसके प्रकाशन की तारीख से दस साल की समाप्ति के बाद लागू होगी।

3. आयोग के निर्देश संख्या 509/241/ECI/LET/FUNC/JUD/RCC/2011 दिनांक 20 अप्रैल, 2018 के पैरा 3 की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है, जो निर्दिष्ट करता है कि

"ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 और इस संबंध में अन्य लागू कानून जो स्थानीय नगरपालिका प्राधिकरण द्वारा अभियान सामग्री के निपटान के लिए अपनाए गए हैं कि प्रदूषण फैलाने वाला भुगतान करेगा सिद्धांत के अनुसार इसकी लागत उम्मीदवारों या राजनीतिक दलों से, जैसा भी मामला हो, वसूल की जाएगी।"

4. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भी पत्र संख्या 12/79/2018-HSMD(Pt.) दिनांक 17 जनवरी, 2019 के माध्यम से आयोग से संपर्क किया था और चुनाव के दौरान स्थायी प्रथाओं का पालन करने और एकल–उपयोग प्लास्टिक के वैकल्पिक विकल्प का उपयोग करने के लिए सभी संबंधित लोगों से अनुरोध पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तदनुसार अपने पत्र दिनांक 26.02.2019 के माध्यम से निम्नानुसार संबोधित किया गया है कि:–

"पोस्टर, कट–आउट, होर्डिंग, बैनर, राजनीतिक विज्ञापन आदि सहित बहुत सारी प्रचार सामग्री प्लास्टिक से बनी होती है। चुनाव के बाद, प्रचार सामग्री को फेंक दिया जाता है और बेकार हो जाती है। ऐसे एकल–उपयोग प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है प्रचार के दौरान एकत्र नहीं किया जाता है और जल निकासी और नदी प्रणालियों के अवरुद्ध होने, आवारा जानवरों द्वारा निगलने, भूमि और जल प्रदूषण, खुली हवा में जलने आदि का कारण बनता है, जिससे मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इनमें से कुछ प्लास्टिक पॉली विनाइल क्लोराइड (PVC) आधारित हैं, जो जलने पर विषाक्त उत्सर्जन पैदा करता है।

प्रचार सामग्री में प्लास्टिक के उपयोग के कई वैकल्पिक विकल्प उपलब्ध हैं जैसे कि कंपोस्टेबल प्लास्टिक, प्राकृतिक कपड़े, पुनर्नवीनीकरण कागज सामग्री आदि, जिनका पर्यावरणीय प्रभाव कम होता है। ऐसी सामग्रियों को एक टिकाऊ और पर्यावरण की दृष्टि से सुदृढ़ प्रबंधन अभ्यास के रूप में बढ़ावा देने की आवश्यकता है। आगामी आम चुनाव चुनाव प्रचार में व्यवहारिक बदलाव लाने और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रस्तुत करते हैं।"

5. माननीय केरल उच्च न्यायालय ने भी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा चुनाव प्रचार में प्लास्टिक के उपयोग पर ध्यान दिया है और निम्नलिखित मामलों में याचिकाओं का निपटारा करते हुए आदेश पारित किए हैं:

(i) In the Order dated n" March, 2019 passed by the Kerala High Court in WP(C) No. 7193 of2019 (B.S.Syamkumar Vs. State of Kerala & Others), has taken note of the Commission's direction in the letter No. 4/3/2019/SDR dated 26.02.2019 regarding making our elections eco-friendly and passed the following Order: -

"..... We also deem it appropriate to order that all candidates and the National/State Political Parties must strictly adhere to the aforequoted guidelines of the Election Commission, so that only the eco-friendly materials are used during the election campaign and there is no use of pvc Flex Boards and other such non bio-degradable materials as campaign material, **in the State of Kerala**. "

(ii) In the Order dated 26th February, 2019 and 25th March, 2019 the Hon'ble Kerala High Court in WP(C) No. 22750 of 2018 (St. Stephen's Malankara Catholic Church Vs. State of Kerala & Ors.) has inter-alia given the following directions: -

"5.....I direct all the District Collectors; who are also the designated District Election Officers, to ensure that the directions of this Court in the interim order, dated 26.02.2019, are implicitly implemented with respect to election campaign materials and that any unauthorized Board/Banner/Flag, installed by any political party/entity, in violation of the orders of this court and that of the learned Division Bench be forthwith removed and returned to the parties/entities, who have installed it and initiatefurther action as has been Page 3 of 4 directed in paragraph 10(c) of the order of this Court dated 26.02.2019. Obviously, therefore, the concerned District Collector will have to charge the person/entitites, the applicable tariff and penalty for installing these illegal Boards and further initiate action for recovery; and as I have already ordered in the afore mentioned interim order, the said Authorities will be personally held responsible if this is not done. Further, they will also fully accountable to this Court, if an appropriate criminal case, either under the Indian Penal Code or

under the National Highway Act or under the Police Act, is not registered against the installation of these Boards/Banners/Flags and the concerned Station House Officer of the local Police Station will ensure that suitable FIR is registered in terms of these directions, when duly approaded. "

6. पर्यावरण की रक्षा करना कोई व्यक्तिगत कार्य नहीं बल्कि एक सामूहिक जिम्मेदारी है और इसलिए चुनाव आयोग सभी राजनीतिक दलों से चुनाव प्रचार के दौरान पोस्टर, बैनर आदि की तैयारी के लिए प्लास्टिक/पॉलिथीन और इसी तरह की गैर–बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों के उपयोग से बचने का आग्रह करता है जो पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के हित में हो।

अतः आयोग के प्रतिबंधित प्लास्टिक के संबंध में जारी निर्देश दिनांक 18 अगस्त, 2023 एवं दिनांक 12.08.2021 की अधिसूचना का भली भाँति अध्ययन कर लिया जावें एवं चुनाव संबंधी प्राधिकारियों के ध्यान में लाया जावें तथा राजनैतिक दलों और उनके द्वारा खड़े किए जाने वाले अभ्यर्थियों को एवं निर्दलीय अभ्यर्थियों को उक्त आयोग के निर्देशों की प्रतिलिपि नोमिनेशन के दौरान या संवीक्षा के तुरन्त पश्चात् उपलब्ध करा दी जावें और उनके द्वारा की जाने वाली पालना से उन्हे अवगत कराते हुए आगामी विधानसभा आम चुनाव, 2023 में आयोग के संदर्भित निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करवाई जावें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(प्रवीण गुप्ता)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक एफ 3(1)(1) प्रथम/निर्वा./2023/3996 जयपुर, दिनांक 24/8/23

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
3. सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी(स्टोर), राजस्थान, जयपुर।

विशेषाधिकारी, निर्वाचन विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

Speed Post/E-mail

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No.3/ER/2023/SDR/Vol.II Dated: 18th August, 2023

To,

The President/General Secretary of
Recognized National and State Political Parties

Subject: Making election campaign eco friendly– Consolidated instructions- regarding.

Ref: 1. Commission's letter no. 4/3/99/JS.II, dated 16.07.1999
2. Commission's letter no. 4/3/2003/JS.II/Vol.I, dated 01.05.2003
3. Commission's letter no. 4/3/2004/JS.II/Vol.I, dated 11.03.2004
4. Commission's letter no. 4/3/2006/JS.II, dated 16.03.2006
5. Commission's letter no. 4/3/2016/SDR, dated 05.04.2016
6. Commission's letter no. 4/3/2019/SDR, dated 26.02.2019,
7. Commission's letter no. 3/ER/2019/SDR/Vol.II, dated 19.03.2019
8. Commission's letter no. 3/ER/2019/SDR/Vol.II, dated 02.04.2019 (Sent to CEO Kerala), and
9. Commission's letter no. 3/ER/2019/SDR/Vol.II, dated 09.09.2021

Madam/Sir,

In today's world, the environmental concerns have become more significant, Election Commission is also very concerned with the issue of environment hazards caused by use of non-biodegradable materials in elections. The Commission has been urging all political parties and candidates to avoid the use of plastic/polythene for preparation of posters, banners etc. during election campaign, since 1999.

2. Para 4(b) of the Notification No. G.S.R. 571(E) dated 12.08.2021 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change amending the Plastic Waste Management Rules, 2016, provides that-

> *"(2) The manufacture, import, stocking, distribution, sale and use of following single use plastic, including polystyrene and expanded polystyrene, commodities shall be prohibited with effect from the 1st July, 2022:-*
>
> *(a) ear buds with plastic sticks, plastic sticks for balloons, plastic flags, candy sticks, ice-cream sticks, polystyrene [Thermocol] for decoration;*

(b) plates, cups, glasses, cutlery such as forks, spoons, knives, straw, trays, wrapping or packing films around sweet boxes, invitation cards, and cigarette packets, plastic or PVC banners less than 100 micron, stirrers.

(3) The provisions of sub-rule (2) (b) shall not apply to commodities made of compostable plastic.

(4) Any notification prohibiting the manufacture, import, stocking, distribution, sale and use of carry bags, plastic sheets or like, or cover made of plastic sheets and multilayered packaging and single-use plastic, including polystyrene and expanded polystyrene, commodities, issued after this notification, shall come into force after the expiry of ten years, from the date of its publication".

3. Attention is also drawn to Para 3 of the Commission's instruction No. 509/241/ECI/LET/FUNC/JUD/RCC/2011 dated 20th April, 2018, which specifies that

"The Solid Waste Management Rules, 2016 and the Plastic Waste Management Rules, 2016 and other applicable laws in this regard are hereby adopted for disposal of the campaign material by the local municipal authority and the cost for the same shall be recovered from the candidates or political parties, as the case may be, in accordance with the polluter pays principle."

4. The M/o Environment, Forest and Climate Change had also approached the Commission vide letter no. 12/79/2018-HSMD(Pt.) dated 17th January, 2019 with the request to impress upon all concerned to follow sustainable practices and use alternate option to single-use plastic during elections and accordingly the Commission vide its letter dated 26.02.2019 addressed as under:

"A lot of the campaigning material including posters, cut-outs, hoardings, banners, political advertisements, etc., is made of plastic. After the elections, the campaigning materials, are discarded and become waste. Such single-use plastic waste generated during campaigning does not get collected and causes choking of drainage and river systems, ingestion by stray animals, land and water pollution, open air burning, etc. leading to adverse impacts on human health and environment. Some of these plastics are Poly Vinyl Chloride (PVC) based, which produces toxic emissions on burning.

A number of alternate options to use of plastic in campaigning material are available such as compostable plastics, natural fabrics, recycled paper material etc., which have a lesser environmental impact. Such materials need to be promoted as a sustainable and environmentally sound management practice. The upcoming General Elections present an excellent opportunity to introduce a behavioral change in election campaigning and to promote sustainable practices."

5. The Hon'ble Kerala High Court has also taken note of the use of plastics in election campaigns by the political parties and candidates and passed orders while disposing the petitions in the following cases: -

(i) In the Order dated 11th March, 2019 passed by the Kerala High Court in WP(C) No. 7193 of 2019 (B.S.Syamkumar Vs. State of Kerala & Others), has taken note of the Commission's direction in the letter No. 4/3/2019/SDR dated 26.02.2019 regarding making our elections eco-friendly and passed the following Order: -

"..... We also deem it appropriate to order that all candidates and the National/State Political Parties must strictly adhere to the aforequoted guidelines of the Election Commission, so that only the eco-friendly materials are used during the election campaign and there is no use of PVC Flex Boards and other such non bio-degradable materials as campaign material, ***in the State of Kerala****."*

(ii) In the Order dated 26th February, 2019 and 25th March, 2019 the Hon'ble Kerala High Court in WP(C) No. 22750 of 2018 (St. Stephen's Malankara Catholic Church Vs. State of Kerala & Ors.) has inter-alia given the following directions: -

"5.....I direct all the District Collectors; who are also the designated District Election Officers, to ensure that the directions of this Court in the interim order, dated 26.02.2019, are implicitly implemented with respect to election campaign materials and that any unauthorized Board/Banner/Flag, installed by any political party/entity, in violation of the orders of this court and that of the learned Division Bench be forthwith removed and returned to the parties/entities, who have installed it and initiate further action as has been

directed in paragraph 10(c) of the order of this Court dated 26.02.2019. Obviously, therefore, the concerned District Collector will have to charge the person/entitites, the applicable tariff and penalty for installing these illegal Boards and further initiate action for recovery; and as I have already ordered in the afore mentioned interim order, the said Authorities will be personally held responsible if this is not done. Further, they will also fully accountable to this Court, if an appropriate criminal case, either under the Indian Penal Code or under the National Highway Act or under the Police Act, is not registered against the installation of these Boards/Banners/Flags and the concerned Station House Officer of the local Police Station will ensure that suitable FIR is registered in terms of these directions, when duly approaded."

6. Protecting the environment is not an individual task but a collective responsibility and hence the Election Commission urges all the political parties to avoid the use of plastic/polythene and similar non-biodegradable materials for preparation of posters, banners, etc. during election campaign in the interest of environment and human health.

Yours faithfully,

(S. B. Joshi)
Principal Secretary

Copy to : - The Chief Electoral Officers for information. The CEOs are requested that the content of this instruction shall be brought to the notice of all DEOs, ROs, other election authorities, candidates and registered unrecognized political parties based in your State/UT.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12082021-228947
CG-DL-E-12082021-228947

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 459] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 12, 2021/श्रावण 21, 1943
No. 459] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 12, 2021/SHRAVANA 21, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2021

सा.का.नि. 571(अ).—प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 को संशोधन करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 169 (अ) द्वारा तारीख 11 मार्च, 2021 में प्रारूप नियम प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उन सभी लोगों से, जो उन नियमों से प्रभावित हो सकते हैं, उक्त प्रारूप नियम को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप नियमों को अंतर्विष्ठ करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 11 मार्च, 2021 को उपलब्ध कराई गई थी;

और, उपर्युक्त अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार किया गया है;

अत:, अब केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, धारा 8 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2021 कहा है।

(2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों को कहा गया है) में, नियम 2 में, उप-नियम (1) में, "आयातकों" शब्द के पश्चात् "ब्राण्ड स्वामी, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता (पुनर्चक्रक, सह-प्रसंस्करणकर्ता आदि)" शब्द अंत:स्थापित किया जाएगा।

उक्त नियमों में, नियम 3 में –

(i) खंड (ढ) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

'(ढ क) "बिना बुने प्लास्टिक बैग" – से अभिप्रेत है जो यांत्रिक अथवा थर्मल अथवा रासायनिक साधनों द्वारा एक-साथ बंधे हुए जटिल प्लास्टिक फाइबरों या तंतुओं (और छिद्रित फिल्मों द्वारा) की प्लास्टिक की शीट अथवा वेब आकार के कपड़े से बने हुए बिना बुने प्लास्टिक के बैग और "बिना बुने कपड़े" से अभिप्रेत है जिसमें एक समतल अथवा गुच्छेदार छिद्रयुक्त शीट जो सीधे प्लास्टिक फाइबरों, पिघले हुए प्लास्टिक अथवा प्लास्टिक की फिल्मों से बनाया जाता है;

(ii) खंड (थ) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

'(थ क) "प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण" – से अभिप्रेत है जिससे कोई ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट को पुन:उपयोग, पुनर्चक्रण, सह-प्रसंस्करण अथवा नए उत्पादों में परिवर्तन के प्रयोजन के लिए प्रबंधित किया जाता है; ';

(iii) खंड (फ) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

'(फ क) "एकल प्रयोग प्लास्टिक से बनी वस्तु" का अर्थ है – जिससे प्लास्टिक की मद, जिसके निपटान अथवा पुनर्चक्रण से पहले उसे एक ही प्रयोजन के लिए एक बार ही उपयोग किया जाना है;

(फ ख) "थर्मोसेट प्लास्टिक" से अभिप्रेत है जिसमें ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर अपरिवर्तनीय रूप से कठोर हो जाता है और इसलिए इसे वांछित आकार में नहीं बदला जा सकता है;

(फ ग) "थर्मोप्लास्टिक" से अभिप्रेत है जिसमें ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर नरम हो जाता है और इसे वांछित आकार में ढाला जा सकता है;'

4. उक्त नियमों में, नियम 4 में –

(क) उप-नियम (1) में, - (i) "आयातक भंडारण" शब्दों के स्थान पर "आयात, भंडारण" शब्द रखें जाएंगे;

(ii) खंड (ग) में, "पचास माइक्रोन की मोटाई", शब्दों के स्थान पर, शब्द आंकड़े, अक्षर और कोष्ठक "30 सितम्बर 2021 से पचहत्तर माइक्रोन की मोटाई और 31 दिसम्बर, 2022 से एक सौ बीस (120) माइक्रोन की मोटाई" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) खंड (ज), "कैरी बैगों", शब्दों के बाद, "और वस्तु" शब्द अंतर्विष्ट किए जाएंगे;

(iv) खंड (ज), "कंपोस्ट योग्य प्लास्टिक कैरी बैगों", शब्दों के बाद, "या वस्तु या दोनों" शब्द अंतर्विष्ट किए जाएंगे;

(v) खंड (झ) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

"(ञ) 30 सितम्बर, 2021 की तारीख से गैर-बुना हुआ प्लास्टिक कैरी बैग 60 ग्राम प्रति वर्ग मीटर (जीएसएम) से कम नहीं होगा।";

(ख) उप-नियम (1) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

"(2)" 1 जुलाई, 2022 की तारीख से पोलीस्टाइरीन और विस्तारित पोलीस्टाइरीन वस्तुओं सहित निम्नलिखित एकल-प्रयोग-प्लास्टिक वस्तुओं के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग का निषेध किया जाएगा:-

(क) प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडिया, पोलीस्टाइरीन (थर्मोकोल) की सजावटी सामग्री;

(ख) प्लेटें, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे जैसे कटलरी, मिठाई के डिब्बों के इर्द-गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, स्ट्रिर।

(3) उप-नियम (2) (ख) के उपाबंध, कंपोस्ट योग्य प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुओं पर लागू नहीं होंगे।

(4) इस अधिसूचना के बाद कैरी बैग, प्लास्टिक शीट या समान प्रकार की सामग्री या प्लास्टिक शीट और बहु-परतीय पैकेजिंग से बने कवर और पोलिस्टाइरीन और विस्तारित पोलिस्टाइरीन, वस्तुओं सहित एकल प्रयोग के प्लास्टिक के विनिर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण, विक्रय और उपयोग को निषिद्ध करने के संबंध में, जारी की गई कोई भी अधिसूचना, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दस वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात लागू होगी।

5. उक्त नियमों में, नियम 5 में, उप-नियम (1) में, खण्ड (घ) में "2000" अंकों के स्थान पर "2016" रखा जाएगा।

6. उक्त नियमों, में, नियम 6 में, उप-नियम (2) में, खण्ड (क) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड अंत-स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(क क) सुनिश्चित करना कि इन यथा संशोधित नियमों के उपबंधों का अनुपालन किया जाए।

7. उक्त नियमों में नियम 7 में, उप-नियम (1) में, खण्ड (क) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(क क) सुनिश्चित करना कि इन यथा संशोधित नियमों के उपबंधों का अनुपालन किया जाए।

8. उक्त नियमों में, नियम 9 में, उप-नियम (1) में, "संबंधित स्थानीय निकाय" शब्दों के पश्चात, "इन नियमों के अंतर्गत समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

9. नियम 11 में, उप-नियम (1), -

(i) "प्लास्टिक कैरी बैग" शब्दों के पश्चात, "प्लास्टिक पैकिंग" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ii) खंड (क) में "विनिर्माता" शब्द के पश्चात, "उत्पादक" या ब्रैंड स्वामी" शब्द जोड़े जाएंगे, और "कैरी बैग" शब्द के बाद, "और ब्रैंड के स्वामी द्वारा उपयोग प्लास्टिक पैकिंग" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(iii) खंड (ख), "बहु-परतीय पैकिंग" शब्दों के पश्चात, "आयातित सामग्री के लिए उपयोग बहु-परतीय पैकिंग को छोडकर" अंत:स्थापित किया जाएगा।

(iv) खंड (ग) में, "नाम और प्रमाणपत्र सं." शब्दों के पश्चात, "उत्पादक का" अंत:स्थापित किया जाएगा।

10. नियम 12 में, -

(i) उप-नियम (2) में, "अपशिष्ट जनक" शब्दों के पश्चात, "पर प्रतिबंध या निषेध" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ii) उप-नियम (3) में, "अपशिष्ट जनक" शब्दों के पश्चात, "पर प्रतिबंध या निषेध" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

11. नियम 13, में उप-नियम (1) में, "संबंधित संघ राज्यक्षेत्र" शब्दों के पश्चात, "या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड" अंत:स्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 17-2/2001(पार्ट)पार्ट I-एचएसएमडी]

नरेश पाल गंगवार, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 320(अ) तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात इनमें अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 285(अ) तारीख 27 मार्च, 2018 के द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th August, 2021

G.S.R. 571(E).—Whereas the draft rules to amend the Plastics Waste Management Rules, 2016, were published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 11th March, 2021 vide notification number GSR 169 (E), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of sixty days from the date copies of the Gazette containing the said draft rules were made available to the public;

And whereas, copies of the Gazette containing the said draft rules were made available to the public on the 11th March, 2021;

And whereas, objections and suggestions received within the aforesaid period have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sections 6, 8 and 25 of Environment (Protection) Act 1986, (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Plastic Waste Management Rules, 2016, namely :-

1. (1) These rules may be called Plastic Waste Management (Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Plastic Waste Management Rules,2016 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, in sub-rule (1), after the word "Importers", the words, "brand-owner, plastic waste processor (recycler, co-processor, etc.)" shall be inserted.

3. In the said rules, in rule 3,

(i) after clause (n), the following clause shall be inserted, namely :-

'(na) "Non-woven plastic bag" means Non-woven plastic bag made up of plastic sheet or web structured fabric of entangled plastic fibers or filaments (and by perforating films) bonded together by mechanical or thermal or chemical means, and the "non-woven fabric" means a flat or tufted porous sheet that is made directly from plastic fibres, molten plastic or plastic films;'

(ii) after clause (q), the following clause shall be inserted, namely: -

'(qa) "Plastic waste processing" means any process by which plastic waste is handled for the purpose of reuse, recycling, co-processing or transformation into new products;'

(iii) after clause (v), the following clauses shall be inserted, namely: -

'(va) "Single-use plastic commodity" mean a plastic item intended to be used once for the same purpose before being disposed of or recycled;'

'(vb) "Thermoset plastic" means a plastic which becomes irreversibly rigid when heated and hence cannot be remoulded into desired shape;'

'(vc) "Thermoplastic" means a plastic which softens on heating and can be moulded into desired shape;'.

4. In the said rules, in rule 4, -

(a) in sub-rule (1),-

(i) for the words "importer stocking", the words "import, stocking" shall be substituted;

(ii) in clause (c), for the words "fifty microns in thickness" , the words, figures, letters and brackets "seventy five microns in thickness with effect from the 30th September, 2021and one hundred and twenty (120) microns in thickness with effect from the 31st December, 2022" shall be substituted;

(iii) in clause (h), after the words, "carry bags", the words "and commodities" shall be inserted;

(iv) in clause (h), after the words, "compostable plastic carry bags", the words "or commodities or both" shall be inserted;

(v) after clause (i), following clause shall be inserted, namely: -

" (j) non-woven plastic carry bag shall not be less than 60 Gram Per Square Meter (GSM) with effect from the 30th September, 2021.";

(b) after sub-rule (1), the following sub-ules shall be inserted, namely:-

"(2) The manufacture, import, stocking, distribution, sale and use of following single-use plastic, including polystyrene and expanded polystyrene, commodities shall be prohibited with effect from the 1st July, 2022:-

(a) ear buds with plastic sticks, plastic sticks for balloons, plastic flags, candy sticks, ice-cream sticks, polystyrene [Thermocol] for decoration;

(b) plates, cups, glasses, cutlery such as forks, spoons, knives, straw, trays, wrapping or packing films around sweet boxes, invitation cards, and cigarette packets, plastic or PVC banners less than 100 micron, stirrers.

(3) The provisions of sub-rule (2) (b) shall not apply to commodities made of compostable plastic.

(4) Any notification prohibiting the manufacture, import, stocking, distribution, sale and use of carry bags, plastic sheets or like, or cover made of plastic sheets and multi-layered packaging and single-use plastic, including polystyrene and expanded polystyrene, commodities, issued after this notification, shall come into force after the expiry of ten years, from the date of its publication".

5. In the said rules, in rule 5, in sub-rule (1), in clause (d), for the figures "2000", the figures "2016" shall be substituted.

6. In the said rules, in rule 6, in sub-rule (2), after clause (a), following clause shall be inserted, namely: -

"(aa) ensuring that the provisions of these rules, as amended, are adhered to;".

7. In the said rules, in rule 7, in sub-rule (1), after clause (a), following clause shall be inserted, namely : -

"(aa) ensuring that the provisions of these rules, as amended, are adhered to;".

8. In the said rules, in rule 9, in sub-rule (1), after the words, "local body concerned", the words "as per guidelines issued under these rules from time to time" shall be inserted.

9. In rule 11, sub-rule (1), —

(i) after the words "plastic carry bag", the words, "plastic packaging" shall be inserted;

(ii) in clause (a), after the word "manufacturer", the words "producer or brand-owner" shall be inserted, and after the words "carry bag", the words "and plastic packaging used by the brand owner" shall be inserted;

(iii) in clause (b), after the words "multilayered packaging", the words "excluding multi-layered packaging used for imported goods" shall be inserted;

(iv) in clause (c), after the words "name and certificate number", the words "of producer" shall be inserted.

10. In rule 12, —

(i) in sub-rule (2), after the words "waste generator," ,the words "restriction or prohibition on" shall be inserted;

(ii) in sub-rule (3), after the words "waste generator," ,the words "

restriction or prohibition on" shall be inserted.

11. In rule 13, in sub-rule (1), after the words "Union Territory concerned", the words "or the Central Pollution Control Board" shall be inserted.

[F. No. 17-2-2001 (Pt)-Part I -HSMD]

NARESH PAL GANGAWAR, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number GSR 320 (E), dated the 18th March, 2016 and subsequently amended vide notification number GSR 285 (E), dated the 27th March, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.08.12 22:57:47 +05'30'